(1) महका भारत दि० 2-06-2011

सम्पादकीय

एक और बड़ी योज़ना

मनरेगा के बाद संप्रग सरकार की एक और बड़ी फ्लैगशिप योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए आरंभ हो रही है। इस योजना की शुरुआत का सौभाग्य राजस्थान को प्राप्त हो रहा है। वैसे भी राजस्थान कई बड़ी राष्ट्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों के शुभारम्भ का साक्षी रहा है। फिर चाहे वह पंचायतराज प्रणाली का मामला रहा हो या राजीव गांधी का 21वीं सदी के भारत का सपना रहा हो। संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी राजस्थान के आदिवासी बहुल इलाके बांसवाड़ा में तीन जून को गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों के लिए 3000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नामक संप्रग सरकार की यह नई फ्लैगशिप योजना शुरू कर रही हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं इस आयोजन की तैयारियों पर नजर रख रहे हैं ताकि इसमें कोई कमी न रहे। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की यह योजना मनरेगा के बाद दूसरी महत्वपूर्ण योजना होगी जिससे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आजीविका का सहारा मिल सकेगा। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री विलासराव देशमुख ने दिल्ली में पत्रकारों को इस मिशन की जानकारी देते हुए बताया कि गत वर्ष देश की आर्थिक विकास दर नौ प्रतिशत रही लेकिन देश में गरीबी बढ़ती ही जा रही है जो कि सभी के लिए चिंता का विषय है। गरीबी के इस विस्तार को रोकने के इरादे से ही संप्रग सरकार ने मनरेगा जैसी बड़ी योजना शुरू की थी जिसके सुफल देखने को मिलने लगे हैं। गांवों से मजदूरों के पलायन में कमी आई है और ग्रामीणों को खुद अपने ही गांव में रोजगार के अवसर मिलने लगे हैं। इसलिए सरकार बीपीएल परिवारों के लिए 3000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नामक नई फ्लैगशिप योजना शुरू कर रही है। देशमुख ने बताया कि 1999 में शुरू की गई स्वर्ण जयंती ग्राम योजना को केरल, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, बिहार तथा मध्यप्रदेश में मिली सफलताओं को देखते हुए यह योजना शुरू की जा रही है। इसमें बैंकों के माध्यम से 2.50 लाख रुपए की सबसिडी 'स्वयं सहायता समूह' को रोजगार शुरू करने के लिए दी जाएगी। मनरेगा के समान ही यह योजना राज्यों के जरिए जारी की जाएगी और 260 करोड़ रुपए इसके लिए राज्यों को दे भी दिए गए हैं। सरकार ने इस वर्ष कुल नौ हजार करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च करने का मन्सूबा बनाया है। इस योजना के तहत सात-आठ वर्ष में सात करोड़ बीपीएल लोगों को इसमें शामिल किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में नागरिक समाज, कारपोरेट सैक्टर तथा शैक्षणिक संस्थाओं की भी मदद ली जा रही है। योजना में लोगों का कौशल विकास भी किया जाएगा तथा उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बजट का 15-20 प्रतिशत प्रशिक्षण पर खर्च किया जाएगा। योजना के लिए इस वर्ष बैंकों के जरिए 6800 करोड़ रुपए का कर्ज देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा बनाए गए सामानों की बिक्री के लिए मार्केटिंग पर भी ध्यान दिया जाएगा। इससे बीपीएल के लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। उद्देश्य यह है कि इस योजना का सहारा देकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके और उन्हें इस रेखा से ऊपर लाया जा सके। यह योजना जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पंचायती राज संस्थाओं तथा गैर सरकारी संगठनों के जरिए लागू की जाएगी। इसके लिए देश के 600 जिलों में बैंकों के साथ एक ग्राम्य स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है और हरेक केन्द्र को एक-एक करोड़ रुपए दिए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर स्वयं सहायता समूहों का एक बैंक बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। यह भी अपने आप में एक नया विचार है। सहकारी बैंकों के समान ही यह बैंक भी अपने लक्षित समूह की प्रगति व उन्नति के वचनबद्ध होगा और इससे अन्य बैंकों पर पड़ने वाला विभिन्न योजनाओं का दबाव भी कम होगा। मनरेगा और यह योजना मिलकर ग्रामीण क्षेत्र की कायापलट कर देने वाली योजनाएं साबित हो सकती हैं।

✓ (2) समाचार जगत दि० 2-06-2011

नई निवेश पॉलिसी में उद्यमियों को विशेष पैकेज मिलेगा : गहलोत

अलवर, 1 जून (निसं)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि औद्योगिक क्षेत्र में निवेश बढ़ने के साथ प्रदेश में औद्योगिक विकास का वातावरण बन रहा हैं। उन्होंने कहा कि उद्योगों में नई निवेश की पॉलिसी आ रही हैं जिसमें उद्यमियों को विशेष पैकेज दिया जायेगा।

गहलोत बुधवार को अलवर जिले की तिजारा तहसील क्षेत्र के टपूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र में होण्डा मोटर साइकिल एवं स्कूटर इण्डिया प्रा.लि.के नये संयंत्र के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रुप में सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दो पहिया वाहनों के संयंत्र के साथ होण्डा कार बनाने का संयंत्र भी यहां स्थापित करें, इसमें राज्य सरकार हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि यहां औद्योगिक विकास की विपुल संभावनाएं होने के साथ राजस्थान का भविष्य उज्ज्वल हैं तथा राज्य सरकार उद्योगों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि सन् 2013 तक ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान आत्मनिर्भर बनने जा रहा हैं जिसका लाभ औद्योगिक इकाईयों को मिलने के साथ पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि देश में राज्य को सबसे ज्यादा सूरज की किरणें प्राप्त होती हैं इसलिए यहां सोलर प्लान्ट स्थापित कर पं. जवाहर लाल नेहरु सोलर हब बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा हब में कई बड़े समूह बड़ा निवेश करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सन् 2020 तक प्रदेश बेरोजगारों को सर्वाधिक रोजगार की आवश्यकता होगी इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार युवाओं को सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार मुहैया करवाने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के आईटी सपने को साकार करने के लिए राज्य सरकार प्रौद्योगिक क्षेत्र में नये आयाम स्थापित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास एवं उन्हें सुविधा प्रदान करने के लिए रेल मंत्रालय के साथ राज्य सरकार ने एमओयू पर हस्ताक्षर किये। इससे यहां के औद्योगिक क्षेत्रों को लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रदेश का विभिन्न प्रकार के खनिजों की विपुल भण्डार के कारण यहां अनेक सीमेन्ट प्लान्ट स्थापित हुए। उन्होंने कहा कि बाड़मेर केयर्न एनर्जी के सहयोग से 30 प्रतिशत तेल उत्पादन होने के राज्य सरकार रिफाईनरी स्थापित करवाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत अनेक विकास कार्य होने के साथ रोजगार मुहैया करवाने जा रही हैं तथा राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना बीपीएल स्टेट बीपीएल एवं अन्त्योदय परिवारों को 2 रुपये किलो अनाज वितरण करने ➢शेष पृष्ठ दस पर

नई निवेश पॉलिसी....

के साथ राज्य सरकार 3 वर्ष के अन्दर गरीबों के लिए 10 लाख इन्दिरा आवास मकानों का निर्माण कार्य करवायेगी। उन्होंने आह्वान किया कि समाज शिक्षित बनें आईटी एवं प्रौद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़े अनेक प्रतिभाएं निकल कर देश के विकास को आगे बढायेंगे। उद्योग मंत्री राजेन्द्र पारीक ने कहा है कि प्रदेश में आज दो देशों की संस्कृतियों के द्वारा प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति मिलने के साथ वैश्वीकरण के इस युग में देश व विदेश की आधुनिक वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने कहा कि विश्व के अनेक देशों की कम्पनियां प्रदेश में औधोगिक निवेश में भागीदारी बनने का प्रयास कर रही हैं जिसके कारण देश में राजस्थान औद्योगिक निवेश में प्रथम राज्य बन रहा हैं। उन्होंने होण्डा जापानी कम्पनी से आग्रह किया कि वे यहां जल्दी ही कार प्लान्ट लगायें इसके लिए राज्य सरकार हर संभव मदद करने की कोशिश करेगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ए.ए.खान ने कहा कि होण्डा परिवार द्वारा टपूकड़ा क्षेत्र में दूसरा प्लान्ट चालू होने से यहां लोगों को रोजगार मिलने के साथ यहां एकता प्रोजेक्ट में औद्योगिक क्षेत्रों की मदद ली जायेगी ताकि शिक्षा का बेहतर विकास हो सकें। सांसद जितेन्द्र सिंह ने कहा कि होण्डा कम्पनी की आधुनिक तकनीकी,गुणवत्ता के कारण लोगों का विश्वास बढ़ा हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से अलवर उपयुक्त क्षेत्र हैं। इस अवसर पर होण्डा मोटर साईकिल एवं स्कूटर इण्डिया प्रा.लि.के अध्यक्ष श्री केटा मुरामुस्तु ने बताया कि यहाँ होण्डा कम्पनी द्वारा उच्च तकनीक एवं गुणवत्ता वाले वाहनों का उत्पादन किया जायेगा।

(3) महका भारत दि02-06-2011

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

संप्रग सरकार की नई फ्लैगशिप योजना

नई दिल्ली, 1 जून। गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों के लिये संयुक्त प्रगतिशील सरकार गठबंधन संप्रग तीन जून से 3000 करोड रुपए की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नामक नयी फ्लैगशिप योजना शुरु कर रही है। संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी राजस्थान के आदिवासी बहुल इलाके बांसवाडा में इस महत्वांकाक्षी योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय की यह योजना मनरेगा के बाद दूसरी महत्वपूर्ण योजना होगी जिसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बीपीएल लोगों को आजीविका का सहारा मिल सकेगा।

ग्रामीण विकास मंत्री विलास राव देशमुख ने आज यहां पत्रकारों को इस मिशन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गत वर्ष देश का आर्थिक विकास दर नौ प्रतिशत रहा पर देश में गरीबी बढती ही जा रही है। इसलिए हम 3000 करोड रुपए बीपीएल परिवारों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नामक नई फ्लैगशिप योजना शुरु कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1999 में शुरु स्वर्ण जयंती ग्राम योजना से केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार तथा मध्यप्रदेश में मिली सफलताओं को देखते हुए यह योजना शुरु की जा रही है जिसमें बैंकों के माध्यम से 2.50 लाख रुपये की सबसिडी स्व सहायता ग्रुप को रोजगार शुरु करने के लिये दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्यों के जरिए यह योजना जारी की जाएगी और 260 करोड रुपये हमने राज्यों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष हम कुल नौ हजार करोड रुपये खर्च करेंगे और सात-आठ वर्ष में सात करोड बीपीएल लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। देशमुख ने कहा कि इस योजना में नागरिक समाज, कारपोरेट सेक्टर तथा शैक्षणिक संस्थाओं की भी मदद ली जा रही है। इस योजना में लोगों का कौशल विकास भी किया जायेगा तथा उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बजट का 15-20 प्रतिशत प्रशिक्षण पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष बैंकों के जरिए 6800 करोड रुपये का कर्ज देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि स्वसहायता ग्रुप के सदस्यों द्वारा बनाए गए सामानों की बिक्री के लिए मार्केटिंग पर भी ध्यान दिया जाएगा। इससे बीपीएल के लोग अपने पैरों पर खडे हो सकेंगे। यह योजना जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पंचायती राज संस्थाओं तथा गैर सरकारी संगठनों के जरिये लागू की जाएगी। ग्रामीण विकास सचिव बी के सिन्हा ने कहा कि देश के 600 जिलों में बैंकों के साथ एक ग्राम्य स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है और हरेक केन्द्र को एक-एक करोड रुपये दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि विशेषकर आंध्रप्रदेश में स्वसहायता समूहों ने बहुत अच्छा काम किया है और एक बैंक की स्थापना की है। हम राष्ट्रीय स्तर पर स्व सहायता समूहों का एक बैंक बनाने पर भी विचार कर रहे हैं।